संख्या-365/2026/1911/22-2-2025-17(924)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 06 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नसीबुद्दीन उर्फ नसीम पुत्र श्री बबन उर्फ रफीक, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025) दिनांक-08-09-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नसीबुद्दीन उर्फ नसीम पुत्र श्री बबन उर्फ रफीक, जो बडसू, थाना-रतनपुरी, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल पता-महमूद नगर, थाना-सिविल लाईन, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। रू० पाँच लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 31.10.2006 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति का अपहरण कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं०-339/2007, 341/2007, में भा०द०वि० की धारा-364ए, 392, 411 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं०-01, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-05.06.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी के कारागार से रिहा होने पर भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रू० पाँच लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 31.10.2006 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति का अपहरण कर अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नसीबुद्दीन उर्फ नसीम पुत्र श्री बबन उर्फ रफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नसीबुद्दीन उर्फ नसीम (बन्दी संख्या-16853) पुत्र श्री बबन उर्फ रफीक, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-365/2026/1911(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-365/2026/1911/22-2-2025-17(924)/2023

दिनांक: 06 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नसीबुद्दीन उर्फ नसीम पुत्र श्री बबन उर्फ रफीक, जो बडसू, थाना-रतनपुरी, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल पता-महमूद नगर, थाना-सिविल लाईन, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। रू० पाँच लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 31.10.2006 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति का अपहरण कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं०-339/2007, 341/2007, में भा०द०वि० की धारा-364ए, 392, 411 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं०-01, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-05.06.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी के कारागार से रिहा होने पर भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रू० पाँच लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 31.10.2006 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति का अपहरण कर अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नसीबुद्दीन उर्फ नसीम पुत्र श्री बबन उर्फ रफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।